THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) In respect of the hydel components (the dams and Power House, etc.) there has been delay in the finalisation of pre-qualification tenders in consultation with the World Bank. The delay in the case of irrigation components (the barrage and canal system) is due to provision of inadequate funds in the State plan.

(d) The Project Works are being monitored by the Central Water Commission and the Central Electricity Authority. The State Government have been asked to expedite the finalisation of the tenders and the award of works, and to provide adequate funds for the irrigation component.

हरिजनों पर अत्याचार

1471. **श्री नत्था सिंह** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1986 के "जनसत्ता" में "हरिजन उबरना चाहते हैं, पर वे नहीं" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि अत्याचारों से पीड़ित हरिजनों ने 2 जनवरी, 1986 को प्रधान मंत्री तथा अन्य अधिकारियों को एक अभ्यावेदन भेजकर अपनी दुःख:द कथा कही थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अत्याचारों को समाप्त करने और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सरकार ने 17 अप्रैल, 1986 के "जनसत्ता" समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार देखा है । सरकार ने उक्त समाचार की ओर उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान आकृष्ट किया है ।

(ग) गोरखपुर जिले की बसगांव तहसील के धादोना ग्रामवासी कुछ हरिजनों ने जनवरी, 1986 में हरिजनों पर अत्याचार के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिये थे । ये अभ्यावेदन आवश्यक कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिए गए थे ।

(घ) हरिजनों पर किए जा रहे अत्याचारों को भारत सरकार ने गम्भीर चिन्ता का विषय माना है तथा इस खतरे को दूर करने के लिए कृतसंकल्प है । इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश भेजे गए हैं ।

Vacant Posts of Hindi stenographers, typists/clerks

1472. SHRI PYARELAL KHANDELWAL : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) what is the number of posts of Hindi stenographers and typists/clerks which have been lying vacant in various departments of his Ministry and since when ;

(b) what are the reasons for not filling up these vacancies ; and

(c) whether ary apportunity for promotion has been provided to the clerical staff, if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT) : (a) One post of Hindi typist/Lower Divisior Clerk has been lying vacant in the Indian Bureau of Mines, a subordinate office of the Department of Mines, from August, 1985.

(b) Staff Selection Commission has not been able to make a suitable nomination.